राज एक्सप्रेस, भोपाल 14 SEP 2011

अन्य राज्यों को अनुसरण की दी नसीहत

केंद्र ने माना मप्र को मॉडल राज्य

■ प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल। अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र- छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण के मामले में केंद्र सरकार ने मप्र को मॉडल राज्य माना है और अन्य राज्यों को अनुसरण की सलाह दी है। केंद्र ने वक्फ बोर्ड में कंप्यूटराइजेशन के काम को भी आदर्श करार देते हुए अन्य राज्यों को अमल में लाने की सलाह दी है।

छात्रवृत्ति वितरण में गौरव

यह जानकारी पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण मंत्री अजय विश्नोई ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग के 81 हजार बच्चों को पिछले वर्ष छात्रवृत्ति दी गई थी, इस बार यह आंकड़ा एक लाख से अधिक पहुंच जाएगा। सौ सीटों वाले कन्या छात्रावास के लिए भी जमीन का चयन गीतांजलि कालेज के केंपस में किया गया है। हज हाउस के लिए राजधानी के एयरपोर्ट रोड पर सिंगारचोली में दो एकड़ जमीन आरक्षित कर ली गई है। वहीं इंदौर के खजराना में हज हाउस का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अल्प संख्यकों को भविष्य की दृष्टि से मजबूत करने के लिए स्वरोजगार सुविधा उपलब्ध होगी। दस लाख तक की राशि से रोजगार स्थापित करने वालों को ढाई लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। विश्नोई ने बताया कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 385 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी जा रही है।

जन शिक्षण संस्थान को मिला राष्ट्रपति पुरस्कार

भोपाल (आरएनएन)। जन शिक्षण संस्थान भोपाल को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कौशल विकास क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कृत किया। यह पुरस्कार संस्थान निदेशक राजीव नयन तिवारी ने राष्ट्रपति से प्राप्त किया है। पूर्व मंत्री मुकेश नायक द्वारा स्थापित इस संस्थान को एनएलएमए, यूनेस्को, प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास पुरस्कार-2011 प्रदान किया गया है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मानव संशाधन विकास मंत्रालय के राज्यमंत्री ई. अहमद तथा श्रीमती पुरंदेश्वरी भी उपस्थित थे।